

जीआईएस में हुए एमओयू की मुख्यमंत्री ने की विभागवार/जिलावार समीक्षा, कहा हर एक निवेशक से बनाएं संवाद-संपर्क

15 लाख करोड़ के निवेश की नींव रखेंगे: सीएम



लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब तक 8 माह में एमओयू के क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के बाद 8000 से अधिक परियोजनाएं जमीन पर उतरने को तैयार हैं। हमें न्यूनतम 15 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ सभी विभाग तैयारी तेज कर दें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहन देने के सिलसिले में यथाशीघ्र ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी की जाए।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ विशेष



सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की समीक्षा की।

निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने को तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 10-12 फरवरी को हुई यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का सफल आयोजन हुआ था। तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 39.52 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इससे 1.10 करोड़ नौकरी-रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब उत्तर प्रदेश इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

बैठक कर मुख्यमंत्री ने विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की और क्रियान्वयन के लिए जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 39 लाख 52 हजार करोड़ के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त करने के साथ देश-दुनिया में हो रही उत्तर प्रदेश की प्रशंसा के बीच निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है।

बिना देरी के निवेशकों को दें लाभ: सीएम ने कहा कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सहित सभी सेक्टरल नीतियों का लाभ निवेशकर्ता को बिना विलंब, न्यूनतम ह्यूमन इंटरफेयरेंस के मिलना चाहिए। हर एक निवेशक का ध्यान रखें। उन्हें कहीं कोई असुविधा न हो और निवेश प्रस्ताव सरलता के साथ क्रियान्वित

हो। भूमि उपयोग बदलने की जल्द दें अनुमति: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निवेशकों की जरूरत और प्रदेश हित का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में राजस्व संहिता की धारा-80 के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने पर यथोचित विचार करते हुए उचित

‘स्वच्छता और सुरक्षा का मानक बने छठ महापर्व’

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी छठ पर्व को 'स्वच्छता और सुरक्षा' के मानक पर्व के रूप में आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व पर पूजा, अनुष्ठान के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता का माहौल हो, इसके लिए नगर विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएं। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि लोगों

को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग न करने के लिए जागरूक करें। हर जगह समुचित प्रकाश व्यवस्था कराई जाए। घाटों की साफ-सफाई करा लें। प्रदेश में छठ के बीच स्वच्छता के दृष्टिगत 'स्वच्छ घाट' प्रतियोगिता भी कराई जानी चाहिए। जी-20 और जीआईएस के समय जिस प्रकार पूरे महानगर की सजावट की गई थी, उसे स्थायी रूप देने की आवश्यकता है। राजधानी की लाइफलाइन 'शहीद पथ' को सीसीटीवी से कवर किया जाए।

फैसला लिया जाए। अनेक आवासीय परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद भी अधिभोग प्रमाण पत्र-पूर्णता प्रमाण पत्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्तर पर लंबित हैं। यह स्थिति ठीक नहीं। तत्काल निर्णय लेकर नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करें। सीएम ने निर्देश दिए कि मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ईवी, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, फूड

प्रोसेसिंग, सर्कुलर इकॉनमी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर सेक्टर में उद्यमियों ने रुचि दर्शाई है। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए यह अति आवश्यक है कि निवेशकर्ता से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखा जाए। उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान हो। एनओसी, क्लीयरेंस देने में अनावश्यक देरी न हो।